

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1860/2012/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी, जोधपुर.अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री ट्रेडिंग कम्पनी, गोल बिल्डिंग, सरदारपुरा, जोधपुर.प्रत्यर्थी.

2. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या – 2164/2012/जोधपुर.

मैसर्स श्री ट्रेडिंग कम्पनी, सरदारपुरा, जोधपुर.प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी, जोधपुर.अप्रार्थी.

3. अपील संख्या – 1861/2012/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी, जोधपुर.अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स वैभव ट्रेडिंग एण्ड इंजीनियर्स, सरदारपुरा, जोधपुर.प्रत्यर्थी.

4. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या – 2165/2012/जोधपुर.

मैसर्स वैभव ट्रेडिंग एण्ड इंजीनियर्स, सरदारपुरा, जोधपुर.प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी, जोधपुर.अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

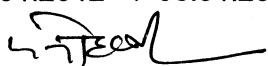
श्री शैलेश सिंघवी, अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/04/2015

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 8 व 9/आरवेट/जेयूसी/12-13 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 31.07.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी राजस्व की अपीलों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा भी वेट अधिनियम की धारा 83(4) के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारीगण की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 23, 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक क्रमशः 17.01.2012 व 06.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।



लगातार.....2

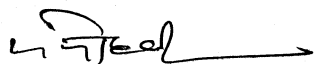
1-2. अपील संख्या - 1860/2012 व 1861/2012/जोधपुर.
3-4. प्रत्याक्षेप (क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स) संख्या - 2164/2012 व 2165/2012/जोधपुर.

2. उपरोक्त दोनों अपीलों एवं प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रार्थना-पत्रों के तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से इन प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2009-10 के लिये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 23, 24 क्रमशः दिनांक 17.01.2012 व 06.01.2012 को पारित करते हुए कर, ब्याज एवं धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33 के सम्बन्ध में दोनों प्रकरणों में पृथक-पृथक संशोधित आदेश दिनांक 28.05.2012 पारित करते हुए कर व ब्याज का समायोजन दिया गया, किन्तु धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को यथावत रखा गया। उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2012 से स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें तथा राजस्व की अपीलों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन्स प्रस्तुत किये गये हैं।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों को समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए शास्ति अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलों स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12 (92)एफ.डी/टैक्स/2011-46 दिनांक 15.09.2011 के द्वारा वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित बिक्री विवरण प्रपत्र दिनांक 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दिये जाने की स्थिति में धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को माफ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा आलौच्य अवधि के समस्त बिक्री विवरण



1-2. अपील संख्या - 1860/2012 व 1861/2012/जोधपुर.
3-4. प्रत्याक्षेप (क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स) संख्या - 2164/2012 व 2165/2012/जोधपुर.

प्रपत्र दिनांक 30.09.2011 से पूर्व ही प्रस्तुत कर दिये गये थे। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसरण में आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने तथा क्रॉस ऑब्जेक्शन्स स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के सन्दर्भ में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92) एफ.डी/टैक्स/2011-46 दिनांक 15.09.2011 का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार है :-

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : 15 सितम्बर, 2011

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(25)एफ.डी./टैक्स/11-169, दिनांक 30.03.2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ऐसे व्यवहारियों, जिन्होंने 30-09-2011 तक वर्ष 2009-2010 से संबंधित समस्त विवरणियां फाइल कर दी हैं और समस्त शोध कर निक्षिप्त करा दिये हैं, द्वारा वर्ष 2009-2010 के लिए संदेय शास्ति की रकम और ब्याज का इसके द्वारा, अधित्यजन करती है।

[सं. एफ.12 (92)एफ.डी/टैक्स/2011-46]

राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर)

(डॉ. रवि कुमार एस.)

शासन उप सचिव

8. इसी प्रकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.16टैक्स/सीसीटी/11-241 दिनांक 16.5.2011 का बिन्दु संख्या 4 व 5 निम्न प्रकार है :-

Hon'ble Chief Minister (Finance Minister) at para 258 of the Budget Speech 2011-12 has announced that :-

4. **Levy of Penalty and Interest.**- The State Government vide notfn No. F.12(25)FD/Tax/11-01 dated 1-4-2011, as amended from time to time [S.No.V613], have waived penalty and interest levied or likely to be levied on filing of late return and/or late payment of tax for the dealers who have submitted their all returns including annual return



लगातार.....4

- 1-2. अपील संख्या - 1860/2012 व 1861/2012/जोधपुर.
3-4. प्रत्याक्षेप (क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स) संख्या - 2164/2012 व 2165/2012/जोधपुर.

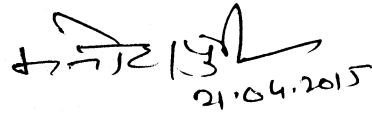
or audit report as the case may be, up to 16.5.2011. Thereafter, no penalty or interest shall be levied on late filing of return or late payment of tax against such dealer(s) on the condition that due tax has been deposited up to 16.5.2011 and all the returns including annual return or audit report, as the case may be, has been submitted up to 16.5.2011.

5. **Procedure of Deemed Assessment.**- In all such cases, the AA shall verify the return in the manner prescribed in clause (3) above and shall make a note on the order sheet, after due verification that the net tax payable by the dealer, as per the return, has been deposited into the exchequer and all the returns including annual return or audit report, as the case may be, has been submitted by the dealer up to 16.5.2011, therefore, the dealer is being assessed with nil demand under the Deemed Assessment Scheme. Copy of such order sheet shall not be made available to the dealer unless directed by the Dy. Commissioner (Admn.)

9. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधि की समस्त विवरणियां दिनांक 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी गयी थीं। ऐसी स्थिति में उक्त अधिसूचना/परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किया जाना, पूर्णतया विधि विरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसरण में धारा 58 की शास्ति अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

10. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन्स का भी तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।


21.04.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य